

(लंचबाद)

11.03.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र (3ए) अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम-

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।
2. न्यायालय सिविल जज (जू.डि.), ललितपुर द्वारा मूलवाद संख्या 450/2022 भूपेन्द्र सिंह बनाम चिकित्साधिकारी आदि में पारित आदेश दिनांकित 09.12.2025 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा विविध दीवानी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के मर्षण हेतु प्रार्थना पत्र (3ए) मय शपथ पत्र (4सी) अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी के प्रार्थना पत्र संख्या 7सी2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं धारा 151 जा.दी. दिनांकित 09.12.2025 को खारिज कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली आदेश हेतु रिजर्व कर ली गयी थी तथा नियत दिनांक पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्तागण के बार-बार पूछने पर आदेश की जानकारी सर्वप्रथम उन्हें दिनांक 08.01.2026 को हुई। उन्होंने आदेश एवं फार्मल आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए नकल विभाग में तुरन्त आवेदन किया और उन्हें दिनांक 17.01.2026 को आदेश एवं फार्मल आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुईं। दिनांक 12.01.2026 से दिनांक 20.01.2026 तक आवेदकगण बीमार होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सके और दिनांक 20.01.2026 को उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। उन्होंने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।
3. विपक्षीगण की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) द्वारा विलंब मर्षण प्रार्थना पत्र (3ए) का मौखिक विरोध किया गया है।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Collector, Land Acquisition Vs. Mst. Kati Ji and others, 1987 (13) AIR 306** में यह विधि व्यवस्था दी है कि *The legislature has Conferred the power to condone delay by enacting section 5 of the Limitation Act of 1963 in order to enable the Courts to do substantial justice to parties by disposing of matters on merit. The expression "sufficient Cause" employed by the Legislature is adequately elastic to enable the Courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice that being the life purpose of the existence of the institution of Courts. It is common knowlege that this Court has been making a justifiably liberal approach does not appear to have percolated down to all the other Court in the hierarchy.* And such a liberal approach is adopted on principle as it is realized that—
 - 1—*Ordinarily, litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late.*
 - 2—*Refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this; when delay is condoned, the highest that can happen is that a cause would be decided on merit after hearing the parties.*
 - 3—*"Every" day's delay must be explained" does not mean that a pedantic approach should be made. Why not every hour's delay, every second's delay? The doctrine must be applied in rational, common sense and pragmatic manner.*
 - 4—*When substantial justice and technical considerations are pitted against each other, the cause of substantial justice deserves to be preferred, for the other side can not claim to have vested right in injustice being done because of a non-deliberate delay.*

5- There is no presumption that delay is occasioned deliberately, or on account of culpable negligence, or on account of malafides. A litigant does not stand to benefit by restoring to delay. In fact, he runs a serious risk.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **N. Balakrishnan Vs. M. Krishnamurthy 1998(7) SCC 123**. के मामले में यह विधि व्यवस्था दी है कि The primary function of court is to adjudicate the dispute between the parties and to advance substantial justice. Time limit fixed for approaching the court in different situations is not because on the expiry of such time a bad cause would transform into a good cause. Rules of limitation are not meant to destroy the right of parties. They are meant to see that parties do not resort to dilatory tactics, but seek their remedy promptly. The object of providing a legal remedy is to repair the damage caused by reason of legal injury. Law of limitation fixes a life-span for such legal remedy for the redress of the legal injury so suffered. Time is precious and the wasted time would never revisit During efflux of time newer causes would sprout up necessitating newer persons to seek legal remedy by approaching the courts. So a life span must be fixed for each remedy. Unending period for launching the remedy may lead to unending uncertainty and consequential anarchy, Law of limitation is thus Founded of public policy."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Smt. Prabha Vs. Ram Prakash Kalra 1987 (Suppl.) SCC 338** में यह विधि व्यवस्था दी है कि the Court should not adopt an injustice oriented approach in rejecting the application for condonation of delay, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Vedabai @ Vijayanatabai Baburao patil Vs. Shantaram Baburao Patil and others 2001 (44) AIR 577 (Sc)** में यह विधि व्यवस्था दी है कि "In exercising discretion under section 5 of the limitation Act, the Courts should adopt a pragmatic approach. A distinction must be made between a case where the delay is inordinate and a case where the delay is of a few days. Whereas in the former case the consideration of prejudice to the otherwise will be a relevant factor so the case calls for a more cautious approach...."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **New India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt Shanti Misra, AIR 1976 SC 237** में यह विधि व्यवस्था दी है कि " discretion given by section 5 (of Limitation Act) should not be defined or crystallized so as to convert a discretionary matter into a rigid rule of law. The express "sufficient cause" Should receive a liberal construction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Shakuntala Devi Jain Vs. Kuntal Kumari, AIR 1969 SC 575** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि" unless want of bona fides of such inaction or negligence as would deprive a party of the protection of section 5 (of Limitation Act) is proved, the application must not be thrown out or any delay can not be refused to be condoned.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **O.P. Kathpalia Vs. Lakhmir Singh AIR 1984 SC 1744** में यह विधि व्यवस्था दी है कि " if the refusal to condone the delay results in grave miscarriage of justice, it would be a ground to condone the delay."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Haribhai Lakhmanbhal Seedhav Vs. State of Gujrat and others 2009 (27) LCD 1645** में विधि व्यवस्था दी है कि the Court should not reject appeal/revision on the ground of delay and the same should be decided on merit.

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त निर्णयज विधि व्यवस्थाओं व मियाद से छूट प्रार्थना पत्र (3ए) के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का परिशीलन किया।

5. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मूलवाद संख्या 450/2022 भूपेन्द्र सिंह बनाम चिकित्साधिकारी आदि में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (7सी2) अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. पर विद्वान सिविल जज (जू.डि.), ललितपुर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 09.12.2025 को पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध वादीगण भूपेन्द्र सिंह आदि द्वारा यह कालबाधित अपील निर्धारित मियाद से 11 दिन के विलंब से दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगण की ओर से कथन किया गया है कि पत्रावली आदेश में रिजर्व होने के कारण उन्हें आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी और आदेश की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 09.01.2026 को हुई और उन्होंने दिनांक 09.01.2026 को ही नकल हेतु आवेदन किया। आदेश की प्रमाणित प्रति उन्हें दिनांक 17.01.2026 को प्राप्त हुई और दिनांक 20.01.2026 को अपील प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा जानबूझकर लापरवाही एवं विलंब नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रति हेतु दिनांक 09.01.2026 को आवेदन किया गया और दिनांक 17.01.2026 को नकल जारी की गयी है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदकगण की ओर से अपील प्रस्तुत करने में लिया गया आधार, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में स्वाभाविक व संतोषजनक है। प्रार्थना पत्र (3ए) शपथ पत्र से समर्थित है और अखण्डित है। अतः अपील को गुणदोष पर निस्तारित करने हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र (3ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (3ए) अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ किया जाता है। पत्रावली वास्ते अंगीकरण दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

दिनांक: 11.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
जिला जज,
ललितपुर।